बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 162 ● नई दिल्ली ● शनिवार 11 अप्रैल 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

राज्यसभा में हरिवंश की हैट्रिक! विदाई के दिन ही मिला 6 साल का नया कार्यकाल, राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए किया मनोनीत

नई दिल्ली। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का बतौर निर्वाचित सदस्य कार्यकाल आज, यानी 10 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। आज उनकी विदाई के मौके पर उन्हें उच्च सदन का एक और कार्यकाल मिल गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें अपने विशेष कोटे से राज्यसभा सांसद चुना है। इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब यह स्पष्ट है कि अगले 6 वर्षों तक उच्च सदन में हरिवंश इस पद को संभालेंगे। हरिवंश के लिए राज्यसभा सदस्य के रूप में यह तीसरा कार्यकाल होगा।

आतंकी साजिश नाकाम- आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले मॉड्यूल का भंडाफोड़, सीसीटीवी से पाकिस्तान भेज रहे थे लाइव फीड

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। स्पेशल सेल ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय जासूसी और हथियारों की तस्करी के मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। यह मॉड्यूल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने दिल्ली और पंजाब से गिरोह के 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। विदेशी और देशी पिस्टल, जिंदा कारतूस और कई संदिग्ध सिम कार्ड भी जब्त किए गए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, स्पेशल सेल की दो टीमों ने एक नेटवर्क ध्वस्त किया है, जिन्होंने आईएसआई की मदद से देश के कई इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। इनका हथियार तस्करी, ग्रेनेड अटैक का भी प्लान था। इन्होंने सौर उर्जा से चलने वाले सीसीटीवी लगाए, जिनकी फीड पाकिस्तान जा रही थी। कई जगह की वीडियोग्राफी भी कराई है, जिनको बाहर भेजा गया है। पंजाब और दिल्ली के लोगों को पकड़ा गया है, ये लोग आर्म्स स्मगलिंग का इस्तेमाल सीसीटीवी लगाने में करते थे। इन कैमरों में रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स लाइव फीड देखते थे। बीकानेर में जहां कैमरा लगा था, वो आर्मी मूवमेंट का मेन रास्ता था। जानकारी के मुताबिक, बेरोजगार युवकों को लालच देकर सीसीटीवी लगवा रहे थे। जांच में सामने आया है कि आर्म्स स्मगलिंग के साथ इनकी तैयारी अब ड्रग्स ट्रैफिकिंग की भी थी। दिल्ली से पकड़ा गया अतुल राठी, आर्म्स स्मगलिंग का काम संभालता था। आपस में बात करने के लिए सोशल मीडिया एप्स का इस्तेमाल करते थे।

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने हाल ही में पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से जुड़े हथियार तस्करी मॉड्यूल का खुलासा कर 10 तस्करों को दबोचा था। आरोपियों के पास से विदेश निर्मित 21 अत्याधुनिक हथियार और 200 कारतूस का जखीरा बरामद किया गया। इनमें सब-मशीन गन, ऑटोमैटिक पिस्तौल शामिल थीं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर निवासी शाहबाज अंसारी इस मॉड्यूल का सरगना है। वह हथियारों की तस्करी करने वाला एक अंतर-राज्यीय अपराधी है, जिस पर कथित तौर पर उत्तरी भारत खासकर दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और आस-पास के राज्यों में सक्रिय आपराधिक गिरोहों को अवैध हथियार पहुंचाने का आरोप है। वह पाकिस्तान से अवैध हथियार और गोला-बारूद मँगवाता था और नेपाल सीमा के रास्ते उन्हें भारत में तस्करी करके लाता था।

अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नया मोर्चा खोलेंगे राघव चड्ढा? वीडियो जारी कर दिए ये संकेत

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व के साथ मतभेदों के बीच, राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर आवाज उठाई, कीमत चुकाई शीर्षक वाला एक वीडियो साझा किया. यह वीडियो संसद में उनके द्वारा विभिन्न मुद्दे उठाते हुए दिखाने वाली कई 'क्लिप' का संकलन है. चड्ढा ने एक वीडियो 'पोस्ट' में कहा, पूरे सम्मान के साथ, मैं मेरे संसदीय प्रदर्शन पर सवाल उठाने वालों से यही कहूंगा कि मेरा काम ही बोलेगा. राघव ने इस वीडियो में उनके राज्यसभा में दिए गए भाषणों की झलक दिखाई गई है, जिसमें उन्होंने कई अहम मुद्दों को उठाया था. वीडियो में डाटा, पितृत्व अवकाश को कानूनी अधिकार बनाने, न्यूनतम बैलेंस पेनल्टी खत्म करने और खाद्य मिलावट जैसे विषय शामिल हैं. इसके अलावा, 28 दिन के मोबाइल रिचार्ज प्लान, एयरलाइंस के एक्स्ट्रा बैगेज चार्ज, पेपर लीक घोटाले और वायु प्रदूषण की समस्या पर भी उन्होंने आवाज उठाई.राघव चड्ढा ने गिग वर्कर्स के शोषण, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में देरी, टोल प्लाजा पर लूट, महंगे एयरपोर्ट खाने और बढ़ते हवाई किराए जैसे मुद्दों को भी संसद में उठाया. उन्होंने मुफ्त वार्षिक हेल्थ चेकअप का अधिकार देने की बात कही. साथ ही डिजिटल कॉपीराइट स्ट्राइक, बढ़ते कर्ज-से-जीडीपी अनुपात और भीड़भाड़ वाले एयरपोर्ट्स की समस्या पर भी चिंता जताई.वीडियो में सरकारी बैंकों की स्थिति, दिव्यांग और सशस्त्र बलों पर टैक्स हटाने, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को वैध बनाने और राइट टू ह्यर, राइट टू फायर जैसे विषय भी शामिल हैं. उन्होंने महंगाई, पंजाब की कैंसर ट्रेन, जल संकट, भूजल की कमी और पीने के पानी की समस्या जैसे गंभीर मुद्दों को भी उठाया है.इसके अलावा शिक्षा और रोजगार के बीच बढ़ती खाई, वेतन इंडेक्सेशन, किसानों के लिए एमएसपी, उत्पादों की भ्रामक ब्रांडिंग, और ग्रामीण बैंकिंग ढांचे को मजबूत करने की जरूरत का जिक्र है. aap ने चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से दो अप्रैल को हटा दिया था. पार्टी ने उन पर आरोप लगाया है कि वह संसद में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्र के खिलाफ मुखर होकर बोलने से बचते रहे और इसके बजाय अपने प्रचार-प्रसार में लगे रहे. चड्ढा ने आक्रामक रुख अपनाते हुए पार्टी के आरोपों को झूठ करार दिया और कहा कि वह संसद में लोगों के मुद्दे उठाने गए थे, हंगामा करने नहीं. राज्यसभा में aap के उपनेता पद से हटाए जाने के बाद से चड्ढा सोशल मीडिया पर कई वीडियो और पोस्ट साझा कर चुके हैं. इससे यह साफ संकेत गया है कि वह उन्हें राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से हटाए जाने के फैसले को चुपचाप स्वीकार नहीं करेंगे.

वकील ने दायर की अलग-अलग 25 जनहित याचिकाएं, पहले भी कर चुके थे अटपटी मांग; अब सुप्रीम कोर्ट ने दी यह सलाह

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को 25 अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर करने वाले वकील को सलाह दी कि उन्हें अदालत में आने के बजाय संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। जैसे ही मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ, याचिकाकर्ता और वकील सचिन गुप्ता ने सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि वह अपनी पीआईएल वापस लेना चाहते हैं। पीठ ने गुप्ता से कहा, आप अपने पेशे पर ध्यान केंद्रित करें। आपको अदालतों में आने के बजाय अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए, उन्हें कुछ मुद्दों पर अधिक जानकारी देनी चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली भी शामिल थे।

अधिकारियों को संवेदनशील बनाने की कीजिए कोशिश - सीजेआई सूर्यकांत

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उचित समय आने पर अगर जरूरत हुई तो न्यायालय उनकी याचिकाओं पर भी विचार करेगा।

सीजेआई सूर्यकांत ने जोर दिया कि एक वकील और कानूनी ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के रूप में याचिकाकर्ता को विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से मुद्दों की पहचान करनी चाहिए और संबंधित अधिकारियों को संवेदनशील बनाने का प्रयास करना चाहिए। पीठ ने कहा कि अगर कुछ नहीं होता है, तो याचिकाकर्ता अदालत का रुख कर सकता है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई 25 पीआईएल वापस लेने की अनुमति दे दी।

किन मामलों पर लगाई थीं जनहित याचिकाएं?

याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई पीआईएल में देश में आधिकारिक उद्देश्यों के लिए एक सामान्य संपर्क भाषा विकसित करने हेतु नीति बनाने और आम जनता के बीच कानूनी ज्ञान फैलाने के लिए टेलीविजन पर कानूनी जागरूकता शो हेतु नीति का मसौदा तैयार करने सहित विभिन्न दिशा-निर्देशों की मांग की गई थी।

पीआईएल में साबुन में इस्तेमाल होने वाले रसायनों के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने और केवल उन्हीं रसायनों की अनुमति देने के लिए नीति बनाने की दिशा में निर्देश शामिल थे जो हानिकारक बैक्टीरिया को मारते हैं, न कि त्वचा के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बैक्टीरिया को। एक अन्य पीआईएल में भिखारियों, ट्रांसजेंडर आदि जैसे वंचित समूहों के उत्थान के लिए नीति बनाने की दिशा में निर्देश मांगे गए थे।

पहले भी खा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से फटकार

गौरतलब है कि नौ मार्च को शीर्ष अदालत ने गुप्ता द्वारा दायर पांच बेकार जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें यह वैज्ञानिक अध्ययन कराने की मांग भी शामिल थी कि क्या प्याज और लहसुन में तामसिक (नकारात्मक) ऊर्जा होती है। उस समय मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा था, आधी रात को यह सब याचिका ड्राफ्ट करते हो क्या? और पीआईएल को अस्पष्ट, बेकार और निराधार करार दिया था। पीठ ने गुप्ता द्वारा दायर चार अन्य पीआईएल को भी खारिज कर दिया था, जिसमें शराब और तंबाकू उत्पादों में कथित तौर पर हानिकारक सामग्री को विनियमित करने के निर्देश मांगे गए थे।

महिला आरक्षण पर जयराम रमेश का पीएम मोदी पर तीखा हमला, बोले- झूठ पर आधारित है सरकार का नैरेटिव

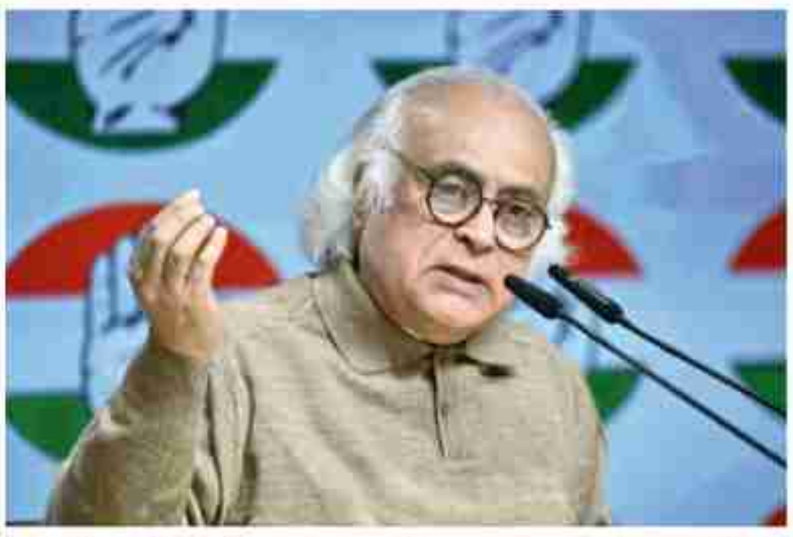

नई दिलली। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) के क्रियान्वयन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पाखंड और धोखे का आरोप लगाया है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट के जरिए सरकार के हालिया यू-टर्न की कड़ी आलोचना की। जयराम रमेश ने दावा किया कि सरकार ने अब महिला आरक्षण को जनगणना और परिसीमन की शर्तों से अलग करने का फैसला किया है। उन्होंने इसे भाजपा की चुनावी हताशा करार देते हुए कहा आगामी विधानसभा चुनावों में हार के डर से प्रधानमंत्री ने अपना रुख बदला है ताकि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में महिला मतदाताओं को लुभाया जा सके। रमेश ने कहा कि जब सितंबर 2023 में यह बिल पास हुआ था, तब कांग्रेस ने इसे 2024 के आम चुनावों से ही लागू करने की मांग की थी। लेकिन तब पीएम ने इसे जनगणना और परिसीमन के बाद (संभवतः 2029) लागू करने की शर्त रखी थी। अब सरकार कह रही है कि जनगणना में बहुत समय लगेगा, जबकि रजिस्ट्रार स्पष्ट कर चुके हैं कि नतीजे 2027 तक आ जाएंगे। ऐसे में अब इसे बिना जनगणना लागू करना सरकार की प्लानिंग की कमी को दर्शाता है। जयराम रमेश ने आशंका जताई कि जल्दबाजी में किए गए परिसीमन से लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो सकती है। यह कदम दक्षिण और पूर्वी भारत के राज्यों (जैसे तमिलनाडु और बंगाल) के राजनीतिक प्रभाव को कम कर सकता है और हिंदी पट्टी के राज्यों का वर्चस्व बढ़ा सकता है। केंद्र सरकार ने 16 अप्रैल से संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें इस अधिनियम में संशोधन पेश किए जा सकते हैं ताकि 2029 तक कोटा सुनिश्चित हो सके। जयराम रमेश ने दोहराया कि कांग्रेस कोटे के भीतर कोटा (OBC महिलाओं के लिए आरक्षण) की अपनी मांग पर कायम है और विशेष सत्र में इस मुद्दे पर मजबूती से लड़ेगी। आज दिल्ली में होने वाली कांग्रेस कार्यसमिति (की बैठक में इस मुद्दे पर अंतिम रणनीति तय की जाएगी।

प्रियदर्शिनी केस- संतोष सिंह की परोल बढ़ाने की मांग खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 के चर्चित प्रियदर्शिनी मट्टू हत्याकांड के दोषी संतोष कुमार सिंह को दी गई परोल की अवधि बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि मामले से जुड़ा मुख्य मुद्दा रिहाई पहले से ही दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि यह मामला 18 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए निर्धारित है। सुप्रीम कोर्ट ने संतोष सिंह को यह स्वतंत्रता दी कि वह हाईकोर्ट से अपने मामले की जल्द सुनवाई की मांग कर सकते हैं। पीठ ने यह भी कहा कि अगर ऐसी मांग की जाती है, तो हाईकोर्ट मामले के तथ्यों को देखते हुए उस पर विचार करे, खासकर यह देखते हुए कि घटना 23 जनवरी 1996 की है और याचिकाकर्ता करीब 31 साल से जेल में है, जिसमें रिमिशन की अवधि भी शामिल है। सुनवाई के दौरान संतोष सिंह के वकील ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने उन्हें आत्मसमर्पण करने का निर्देश देकर कड़ा आदेश दिया है, जबकि वह फिलहाल ओपन जेल में सजा काट रहे हैं, जहां उन्हें रोजाना सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम के लिए बाहर जाने की अनुमति होती है। इससे पहले 19 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने संतोष सिंह को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था और कहा था कि उनकी समयपूर्व रिहाई की याचिका पर विचार आत्मसमर्पण के बाद ही किया जाएगा। इस पर प्रियदर्शिनी मट्टू के भाई ने कड़ा विरोध जताया था और कहा था कि सेंटेंस रिव्यू बोर्ड द्वारा रिहाई की याचिका खारिज करना सही है। गौरतलब है कि 25 वर्षीय प्रियदर्शिनी मट्टू की जनवरी 1996 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। संतोष सिंह, जो उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र थे, को 1999 में निचली अदालत ने बरी कर दिया था, लेकिन 2006 में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला पलटते हुए उन्हें दोषी ठहराया और फांसी की सजा सुनाई। बाद में 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया। पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट ने SRB के उस फैसले को खारिज कर दिया था, जिसमें संतोष सिंह की समयपूर्व रिहाई की मांग ठुकरा दी गई थी। अदालत ने कहा था कि उनके सुधारात्मक व्यवहार का सही मूल्यांकन नहीं किया गया। साथ ही यह भी माना गया कि ओपन जेल में रखा जाना उनके सकारात्मक सुधार का संकेत है।

लद्दाख में 'नकली मंगल ग्रह और अंतरिक्ष'

भारत की स्पेस एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन स्पेस की दुनिया में अपना नाम पूरे विश्व में रौशन कर रहा है। चंद्रयान-3 (2023) चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग, मंगलयान (2014) का पहला प्रयास मंगल की कक्षा में प्रवेश, आदित्य-एल1 (2024) सूर्य मिशन और 2017 में 104 उपग्रहों का रिकॉर्ड लॉन्च शामिल है। 6अगस्त 2024चंद्रयान मिशन चंद्रयान-1 (2008) ने चंद्रमा पर पानी की खोज की। चंद्रयान-3 के साथ, भारत चंद्रमा की सतह पर नरम लैंडिंग वाला चौथा देश और दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग वाला पहला देश बना। मंगलयान (मार्स ऑर्बिटर मिशन 2013)-भारत का पहला प्रयास मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश और विश्व का चौथा देश बना। आदित्य-एल1 (2024)-यह भारत का पहला समर्पित सूर्य वेधशाला मिशन है जो सूर्य का अध्ययन कर रहा है। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने पीएसएलवी सी-37 के माध्यम से एक ही मिशन में 104 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। भारत के पास अपना नेविगेशन सिस्टम है। साथ ही इनसैट और जीसैट श्रृंखला दुनिया के सबसे बड़े घरेलू उपग्रह प्रणाली में से एक है। अब आने वाले कुछ सालों में इसरो का फ्यूचर प्लान इतना शानदार है कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे। इसरो ने इसी कड़ी में इसरो ने लेह में 2से 9 अप्रैल तक'मिशन मित्र' की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को कठिन दूरी के लिए तैयार करना था। यह मिशन विशेष रूप से गगनयान के तहत जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स की टॉलरेंस और मेंटल ट्रेनिंग पर केंद्रित था। 'मिशन मित्र' (मिशन फॉर इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एनालॉग्स) 3500 तक 5000 मीटर की पाइपलाइन पर काम किया। इस दौरान लेह में ऐसा माहौल तैयार किया गया, जिसमें मंगल ग्रह और चंद्रमा जैसा परिदृश्य का अनुभव कराया। इस प्रशिक्षण में हाइपोक्सिया (ऑक्सीजन की कमी), अत्यंत कम अवधि और लंबे समय तक अकेले रहने तक का समरूपता का सामना करना पड़ा है। ग्राउंड पर हीमैटिन स्पेसप्लान्ट सपोर्ट सिस्टम विकसित किया गया, जहां स्पेस जैसी शुरुआत का अभ्यास किया जा सके। विशेषज्ञ के अनुसार, इस तरह के प्रशिक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों की सहनशक्ति, मानसिक संतुलन और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा। नियंत्रित लेकिन यथार्थवादी परिस्थितियों में संचालित ऐसे अनुरूप मिशनों का उपयोग यह समझने के लिए किया जाता है कि गगनयात्री चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कैसा प्रदर्शन करते हैं। मिशन मित्र, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के केव्स एक्सपेरिमेंट के इंटरनेशनल प्रोग्राम से प्रेरणा लेता है। उस एक्सपेरिमेंट में एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस के माहौल की नकल करने के लिए ज़मीन के नीचे की गुफाओं में ट्रेनिंग ली है।इस मिशन के अंतर्गत चार अंतरिक्ष यात्रियों ग्रु शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप की शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और परिचालन क्षमताओं का व्यावहारिक परीक्षणों के माध्यम से परीक्षण किया गया। इसके अलावा उनकी संवाद करने, अनुकूलन करने, तनाव से निपटने और चरम स्थितियों के प्रति उनकी सहनशीलता का भी अवलोकन किया गया। इसरो के अनुसार, भविष्य की मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन में कई महत्वपूर्ण तत्व शामिल होते हैं, जैसे कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चालक दल का प्रदर्शन और ग्राउंड-स्टेशन कर्मचारियों का समर्थन और प्रदर्शन। इसरो ने कहा, मित्र का उद्देश्य गगनयात्रियों और जमीनी नियंत्रण टीमों के बीच टीम अंतर-संचालनीयता और अत्यधिक पर्यावरणीय और परिचालन तनावों के तहत उनके निर्णय लेने की प्रभावशीलता के बारे में महत्वपूर्ण समझ विकसित करना था। इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के नेतृत्व में मित्र का संचालन भारतीय वायु सेना के एयरोस्पेस मेडिसिन संस्थान और बेंगलुरु स्थित प्रोटोप्लेनेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में किया गया। लद्दाख ही क्यों चुना गया ? अंतरिक्ष एक बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण वातावरण प्रदान करता है, जिसके अनुकूल होने के लिए कठोर शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण और अनुकूलन क्षमता की आवश्यकता होती है। इसरो लद्दाख में प्राकृतिक रूप से मौजूद कठोर और चरम वातावरण का उपयोग करके पृथ्वी पर अंतरिक्ष जैसा वातावरण बनाने का प्रयास कर रहा था। लद्दाख समुद्र तल से लगभग 3,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां साल के छह महीने से अधिक समय तक तापमान शून्य से नीचे रहता है, वर्षा बहुत कम होती है, नमी का स्तर निम्न रहता है और साल के अधिकांश महीनों में आसमान बादलों से रहित रहता है ढ्र ये सभी कारक मिलकर लद्दाख को मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियानों के लिए एक आदर्श परीक्षण स्थल बनाते हैं। इसरो ने कहा, लद्दाख में कम तापमान, ऑक्सीजन की कमी और अलगाव, ये सभी अंतरिक्ष उड़ान की स्थितियों के समान थीं। इसी तरह, भारत अब नए तरीके अपना रहा है और एस्ट्रोनॉट की तैयारी के लेवल को बेहतर बनाने के लिए असल दुनिया के माहौल को साइंटिफिक रिसर्च के साथ मिला रहा है।..अंतरिक्ष क्षेत्र में इसरो कॉन्सेप्ट नई ऊंचाई को छू रहा है। इसरो का लक्ष्य है कि 2027 की पहली तिमाही तक इंसानों के साथ गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाए। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। इस मिशन के मुख्य उद्देश्य मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना और साथ ही एक उन्नत बहु-सुरक्षा प्रणाली विकसित करना है और यह वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को भी मजबूत करता है। गगनयान के लिए काफी एक्सपेरिमेंट जोड़े जा रहे हैं और टेक्निकल तैयारी काफी तेज़ी से हो रही है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी अपनी खुद की राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी भी कर रहा है। इसके लिए इसरो ने 2035 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले हिस्से तो 2027 से ही अंतरिक्ष में दिख सकते हैं। इसका मतलब है कि अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन बनाने का पहला कदम अब ज्यादा दूर नहीं है।

तृणमूल और चुनाव आयोग

चुनाव आयोग व ममता दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के बीच कहासुनी व झड़प हुई है, उसे लोकतन्त्र में किसी भी तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसकी मूल वजह यह है कि भारत की दलगत राजनीति में चुनाव आयोग ही ऐसी संस्था है जिस पर विभिन्न पार्टियों की संरचना को वैध रूप देने का भार है। अतः इन दोनों के बीच औपचारिकता का बने रहना बहुत जरूरी है। मगर बीते कल में इन दोनों के बीच जो भी हुआ वह निन्दनीय है, क्योंकि चुनाव आयोग का कार्य उस संवैधानिक जिम्मेदारी से बंधा हुआ है जो राजनीतिक दलों को वैधता प्रदान करता है। दूसरी ओर राजनीतिक दलों का भी कर्तव्य बनता है कि वे चुनाव आयोग की स्वतन्त्रता व निष्पक्षता का सम्मान करें परन्तु कल जिस तरह राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता श्री डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग के साथ हुई संक्षिप्त बैठक के बाद बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने पार्टी के नेताओं से कहा कि वे 'दफा' हो जायें, उससे लगता है कि बैठक का माहौल काफी गरमागरम रहा होगा लेकिन इसके बावजूद देश के चुने हुए लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार शालीनता के दायरे से बाहर है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर अमर्यादित व्यवहार करने का आरोप लगाया है। यदि खबरों को सही मानें तो श्री ज्ञानेश कुमार ने श्री ओब्रायन पर ऊंचा बोलने व हल्ला-गुल्ला करने का आरोप लगाया। इस सन्दर्भ में हमें ध्यान रखना होगा कि श्री ज्ञानेश कुमार को पद मुक्त करने के लिए पिछले दिनों जो प्रस्ताव लोकसभा व राज्यसभा में रखा था उसे दोनों के पीठाधीशवरों ने अस्वीकार कर दिया है। यह प्रस्ताव मूल रूप से तृणमूल कांग्रेस के इसरार पर ही विपक्षी सांसदों ने दिया था। अतः बहुत स्वाभाविक है कि इसे लेकर भी श्री ओब्रायन व उनकी पार्टी के अन्य सांसदों के मन में खटास रही होगी। श्री ओब्रायन के अनुसार चुनाव आयोग का उनकी पार्टी व विपक्ष के प्रति रवैया बहुत ज्यादा बेरुखी का रहा है। उन्होंने कहा कि प. बंगाल की मुख्यमन्त्री व तृणमूल कांग्रेस की सर्वेसर्वा सुश्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पिछले दिनों के भीतर नौ पत्र लिखे मगर इनमें से किसी एक का जवाब तक नहीं आया। उनके अनुसार यदि खत सत्तारूढ़ दल के शीर्षस्थ नेताओं में से किसी एक ने भी लिखा होता तो क्या ज्ञानेश कुमार जवाब न देने की हिमाकत कर सकते थे? लोकतन्त्र में यह वास्तव में चिन्ता का विषय हो सकता है क्योंकि चुनाव आयोग प्रत्यक्ष रूप से सभी राजनीतिक दलों के नियमन के दायित्व से बंधा होता है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा दल सत्ता में है और कौन सा विपक्ष में बैठा हुआ है। इसीलिए समाजवादी चिन्तक व राजनेता स्व. डॉ. राममनोहर लोहिया कहा करते थे कि 'लोकतन्त्र लोकलज्जा' से चलता है। इसका मतलब यही है कि राजनीतिज्ञ अपना फैसला करने से पहले सौ बार सोचें कि उनके किसी भी फैसले में कहीं कोई उनका अपना तो लाभान्वित नहीं हो रहा है। जहां तक स्वतन्त्र संवैधानिक संस्थाओं का सवाल है तो उन्हें हर सूरत में यह विचार करना जरूरी होता है कि उन पर सरकार के पिट्ठू होने का आरोप न लग सके। चुनाव आयोग के सन्दर्भ में यह फार्मूला सत्तारूढ़ दल व विपक्ष को एक ही नजर से न देखने पर लागू होता है। हम सब जानते हैं कि चुनाव आयोग किसी पार्टी की सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होता। उसकी जवाबदेही सीधे आम नागरिकों के प्रति होती है। उसका यह कर्तव्य बनता है कि 18 वर्ष से ऊपर का हर जायज नागरिक वैध मतदाता बने। मगर विपक्ष उस पर आरोप लगा रहा है कि आयोग जो मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम कर रहा है उसमें वह लाखों मतदाताओं के नाम काट रहा है जिससे चुनावों की शुचिता सीधे प्रभावित हो रही है। जबकि चुनाव आयोग कह रहा है कि समय-समय पर उसे विशेष पुनरीक्षण कराने का संवैधानिक हक प्राप्त है। हालांकि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी चला है जिस पर सुनवाई पूरी करके न्यायमूर्तियों ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है। प. बंगाल में यह प्रक्रिया अभी तक जारी है जिसे लेकर तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग को घेरे हुए है। सभी को मालूम है कि आगामी 23 अप्रैल को प. बंगाल विधानसभा के चुनाव का पहला चरण पूरा हो जायेगा। मगर इस राज्य में 24 लाख के करीब मतदाताओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है और तृणमूल के नेतागण कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मुस्लिम मतदाताओं के नाम जानबूझ कर काट रहा है जबकि आंकड़े बताते हैं कि आयोग ने हिन्दू मतदाताओं के नाम भी काटे हैं बेशक मुस्लिम नागरिकों की संख्या काफी अधिक है लेकिन आज का असल मुद्दा चुनाव आयोग व राजनीतिक दलों के बीच के आपसी व्यवहार को लेकर है। अतः बहुत आवश्यक है कि न तो चुनाव आयोग और न ही राजनीतिक दल एक-दूसरे के साथ अमर्यादित व्यवहार करें। यदि श्री ज्ञानेश कुमार तृणमूल नेताओं को बैठक से बाहर चले जाने को कहते हैं तो इससे चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा पर ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर अगर ओब्रायन चुनाव आयोग के दफ्तर में ही यदि ज्ञानेश कुमार पर चिल्लाते हैं तो इसे भी अशोभनीय कहा जायेगा और उनकी पार्टी की छवि ही खराब होगी। इसके साथ यह भी ध्यान में रखा जाना जरूरी है कि लगभग सभी विपक्षी दल चुनाव आयोग पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने के आरोप क्यों लगा रहे हैं? चुनाव आयोग का मुख्य कार्य साफ-सुथरे व भय-हीन चुनाव कराना होता है जिसके लिए आवश्यक है कि उसकी विश्वसनीयता पर कोई भी शक की अंगुली न उठ सके। राजनीति के बदलते दौर में हम अपने लोकतन्त्र को इसी प्रकार मजबूत करके अगली पीढ़ियों को सौंप सकते हैं।

सम्पादकीय...

संस्कृति की मिसाल

हमारे समाज में शादी सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है, इसलिए लोग इसे हमेशा यादगार पल बनाते हैं। रजत शर्मा की बेटी दिशा की शादी एमजे के साथ इन दिनों काफी चर्चा में रही। मेरे पति अश्विनी मित्रा जी के अभिन्न मित्रों में से एक हैं रजत शर्मा। जब रजत, अश्विनी, अरुण जेटली, अमर सिंह, ललित सूरी इकट्ठे होते थे तो वातावरण हंसी-ठहाकों से भर जाता था। राजनीति के साथ बातों के भी खजाने होते थे। रजत की बेटी की शादी 7-8 दिन से शुरू होकर 4 अप्रैल को सम्पन्न हुई। हम सब हर दिन सम्मलित कुछ थकावट महसूस कर रहे थे परन्तु रजत और ऋतु के चेहरे की मुस्कान एक-एक व्यक्ति को पूछना, प्यार और सम्मान देना कहीं कम नजर नहीं आ रहा था। मेरे भी बेटे-बहुओं को बहुत प्यार से बुलाया गया था। रजत और ऋतु की प्रोफेशनल से पर्सनल बनी एक सफल प्रेम कहानी है। उनकी शादी लगभग 25 साल पहले ललित होटल में हुई, जिसका मैं भी एक हिस्सा बनी थी। शादी के बाद पहले रजत की संघर्ष वाली जिन्दगी थी। उनका जीवन हम सबको प्रेरणा देता है। एक साधारण परिवार, 6 भाइयों और एक बहन, सब्जी मंडी के एक कमरे में रहने वाला इन्सान मेहनत से ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। मैं उन्हें तब से देख रही हूं जब वो जी टीवी में शो कर रहे थे। आज उनकी सफलता के पीछे उनकी मजबूत शक्ति, उनकी सहयोगी प्रेरणा और शक्ति उनकी पत्नी ऋतु धवन हैं, जिसके साथ शादी के बाद रजत ने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। उनकी बेटी दिशा की शादी उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृतियों का मिलन है, जिसमें पारम्परिक मूल्यों और आधुनिक सोच का संतुलन दिखा। कई फंक्शन तो रजत के कई परम मित्रों ने किए। सबसे बड़ी बात थी इस शादी में देश का हर एक महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ, प्रधानमंत्री से लेकर कई मंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर मौजूद थे। यही नहीं बॉलीवुड के मशहूर एक्टर, सिंगर सब मौजूद थे। शादी बड़े रीति-रिवाजों और उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृतियों के मिलन को बयां कर रही थी। जहां पारम्परिक मूल्यों और आधुनिक सोच का संतुलन भी दिखा। रजत-ऋतु की सफलता और विनम्रता वहां सभी वीआईपी और मित्रों की मौजूदगी को बता रही थी। मैंने एक-एक पल का आनंद लिया। क्योंकि यह एक आदर्श और संस्कारों से जुड़ी आधुनिक और पारम्परिक शादी थी। दोनों बच्चों यानी दिशा और एमजे की जोड़ी इतनी प्यारी लग रही थी, जैसे राम-सीता की जोड़ी। रजत-ऋतु के अनुसार दिशा ने कभी साड़ी नहीं पहनी परन्तु क्या उसने साउथ इंडियन कांजीवरम साड़ियां पहनीं, गोल्ड ज्वैलरी का जवाब नहीं था। रजत के अनुसार किस समय दिशा को क्या पहनना है, कैसा दिखना है सब ऋतु ने बड़े दिल से प्लान किया। एक भारतीय बेटी जिसका पिता उसे बार-बार निहार कर खुश भी हो रहा था, तो कभी-कभी आंखें भी नम थीं। कुल मिलाकर यह एक भव्य शादी थी। दो परिवारों को गहराई से जोड़ रही थी।

एक बिल और अनेक वोट

सरकार के लिए 25 मार्च, संभवतः, विदेशी फंडिंग के संदर्भ में एक नई शुरूआत का प्रतीक होता। यह उस विधेयक के कारण था जिसे सरकार संसद में पेश कर उस पर चर्चा करना चाहती थी।

राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी सीपीआई (एम) और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रस्तावित विधेयक का कड़ा विरोध किया है और भाजपा पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। विपक्ष के शोर-शराबे से अधिक महत्वपूर्ण केंद्र सरकार का विधेयक को स्थगित करने का फैसला है, या यूं कहें कि उसे फिलहाल रोक देना। क्या यह संभावित जन-विरोध के डर से किया गया या चुनावी राज्य केरल में राजनीतिक नुकसान से बचने के लिए? यह सर्वविदित है कि केरल, जिसे अब 'केरलम' कहा जाता है, भाजपा के लिए चुनावी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य में उसकी सीमित उपस्थिति और 15 प्रतिशत से अधिक वोट शेयर को सीटों में बदलने में बार-बार असफलता भी एक सच्चाई है जिसे बदलने की वह लगातार कोशिश कर रही है।

हालांकि, घटनाक्रम में अचानक मोड़ आया और इस पर चर्चा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। यह कदम रणनीति का हिस्सा था या आगामी राज्य चुनावों पर संभावित प्रभाव को देखते हुए लिया गया, यह अभी भी बहस का विषय बना हुआ है। इस महीने असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इनमें से इस महीने के अंत में चुनाव होने वाले राज्यों में केरल में ईसाई समुदाय की संख्या उल्लेखनीय है और वह चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में, जबकि सरकार यह कह रही है कि विधेयक को स्थगित करना केवल विधायी प्राथमिकता के कारण था, जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, न कि चुनावी राजनीति के चलते। महत्वपूर्ण राज्य केरल में 9 अप्रैल को मतदान हुआ है और यह सर्वविदित है कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भाजपा दक्षिणी राज्य केरल में किसी बड़ी सफलता के लिए बेताब है। साथ ही, वह काफी समय से ईसाई समुदाय को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में इस महत्वपूर्ण समय पर समुदाय की ओर से किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया या विरोध का सामना करना भगवा पार्टी के लिए न तो संभव है और न ही वह ऐसा जोखिम उठा सकती है। इसी कारण, कहने का तात्पर्य है कि विधेयक को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। प्रस्तावित विधेयक, जिसे चर्चा के लिए पेश किया जाना था लेकिन स्थगित कर दिया गया, ने राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई, जहां विपक्ष ने संसद परिसर में विरोध- प्रदर्शन किया। उन्होंने विधेयक को वापस लेने की मांग की। उनकी शिकायतें थीं विधायी शक्तियों का अत्यधिक हस्तांतरण, कठोर कानून को थोपने का प्रयास, सरकार की आलोचना करने वाले एनजीओ और संगठनों के खिलाफ इसके चयनात्मक उपयोग का खतरा, तकनीकी या मामूली त्रुटियों पर भी सरकार को संपत्ति जब्त करने का अधिकार, संशोधनों को जबरन पारित करने की कोशिश, पारदर्शिता से जुड़ी चिंताएं आदि। अंतिम बिंदु पर लाइसेंस रद्द किए जाने से संबंधित आंकड़े प्राप्त करने और एफसीआरए डैशबोर्ड तक पहुंचने के प्रयास विफल रहे हैं।

सरकार का कहना है कि एफसीआरए विधेयक का उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना है और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाया जा रहा है। तर्क-वितर्क से इतर, यह विधेयक विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 में संशोधन करने का प्रस्ताव रखता है। रिकॉर्ड के लिए, एफसीआरए, 2010 एक ऐसा कानून है जिसे व्यक्तियों, संघों और कंपनियों द्वारा विदेशी अंशदान या आतिथ्य को स्वीकार करने और उसके उपयोग को विनियमित करने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी धन का उपयोग राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल गतिविधियों को प्रभावित न करे। इस कानून के तहत एनजीओ को विदेशी धन प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। संशोधन में प्रस्तावित सबसे बड़ा बदलाव नामित प्राधिकरण का गठन है। यह प्राधिकरण एनजीओ का एफसीआरए पंजीकरण समाप्त होने, रद्द होने या स्वेच्छा से समर्पित किए जाने की स्थिति में उनके विदेशी धन और संपत्तियों पर अस्थायी या स्थायी नियंत्रण ले सकेगा। व्यावहारिक रूप से इसका अर्थ यह होगा कि विदेशी दान से आंशिक रूप से बने स्कूल, अस्पताल, छात्रावास या कल्याण केंद्र सरकार के नियंत्रण में लिए जा सकते हैं। किसी भी बिक्री या हस्तांतरण से प्राप्त धन भारत की संचित निधि में जाएगा, जो केंद्र सरकार का प्रमुख खाता है।

सरकार का मत है कि यह कानून विदेशी धन के दुरुपयोग पर रोक लगाएगा, खामियों को दूर करेगा और किसी एनजीओ का लाइसेंस समाप्त होने की स्थिति में विदेशी वित्तपोषित संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा। सरकार का यह भी कहना है कि यह विधेयक ऐसे परिसंपत्तियों की निगरानी और निपटान के लिए एक उचित ढांचा तैयार करता है। गृह मंत्रालय के अनुसार, वर्तमान में लगभग 16,000 संगठन एफसीआरए के तहत पंजीकृत हैं और सामूहिक रूप से हर वर्ष करीब 22,000 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करते हैं। ऊपरी तौर पर यह तर्कसंगत, आवश्यक और स्पष्ट रूप से सद्भावनापूर्ण प्रतीत होता है लेकिन विपक्ष इससे सहमत नहीं है। जहां केंद्र का तर्क है कि मौजूदा कानून यह स्पष्ट नहीं करता कि किसी एनजीओ का लाइसेंस समाप्त होने पर विदेशी वित्तपोषित संपत्तियों का क्या होता है, वहीं विपक्ष का कहना है कि यह कानून अल्पसंख्यक समुदायों, विशेषकर ईसाइयों द्वारा संचालित संस्थानों को प्रभावित करेगा। यही इस पूरे विवाद का मुख्य बिंदु प्रतीत होता है। तथ्य यह है कि केंद्र द्वारा विधेयक को स्थगित करना इसे एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता से अधिक राजनीतिक मजबूरी की ओर संकेत करता है। दरअसल, यदि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बयान को आधार माना जाए, तो विधेयक इसलिए नहीं लाया जा सका क्योंकि विपक्षविशेष रूप से कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने चुनावों को ध्यान में रखते हुए केरल के लोगों को गुमराह किया। इसे केरल के चर्च नेताओं की उस चेतावनी के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि यह विधेयक पारित होता है तो विदेशी दान से बने स्कूल, अस्पताल और परोपकारी संस्थाएं सरकारी नियंत्रण में आ सकती हैं। केरल में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर यह विवाद एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी सीपीआई (एम) और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रस्तावित विधेयक का कड़ा विरोध किया है और भाजपा पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। विपक्ष के शोर-शराबे से अधिक महत्वपूर्ण केंद्र सरकार का विधेयक को स्थगित करने का फैसला है, या यूं कहें कि उसे फिलहाल रोक देना। क्या यह संभावित जन-विरोध के डर से किया गया या चुनावी राज्य केरल में राजनीतिक नुकसान से बचने के लिए? यह सर्वविदित है कि केरल, जिसे अब 'केरलम' कहा जाता है, भाजपा के लिए चुनावी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य में उसकी सीमित उपस्थिति और 15 प्रतिशत से अधिक वोट शेयर को सीटों में बदलने में बार-बार असफलता भी एक सच्चाई है जिसे बदलने की वह लगातार कोशिश कर रही है। ऐसे में केरल जैसे महत्वपूर्ण राज्य में ईसाई वोट का महत्व और विवादित विधेयक पर पीछे हटने का कदम, जिसे ईसाई समुदाय के नेताओं ने आलोचना का विषय बनाया है, विशेष रूप से प्रासंगिक हो जाता है। केरल की जनसंख्या में ईसाइयों की हिस्सेदारी लगभग 18फीसदी है। कोट्टायम, इडुक्की और एर्नाकुलम जैसे जिलों में उनका खासा प्रभाव है। यदि भाजपा इन क्षेत्रों में ईसाई मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में सफल होती है तो वह इस महत्वपूर्ण राज्य में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की उम्मीद कर सकती है। इस पृष्ठभूमि में यदि भाजपा ने केरल विधानसभा चुनावों से पहले एफसीआरए विधेयक को आगे बढ़ाया होता तो यह उसके लिए उल्टा पड़ सकता था। इसी कारण विधेयक को स्थगित करने का निर्णय लिया गया लेकिन इस बिंदु पर एक सवाल उठता है क्या इससे वास्तव में कोई फायदा होगा? विदेशी फंडिंग को निशाना बनाकर क्या भाजपा ने मतदाताओं को यह संकेत नहीं दे दिया है कि वह मौजूदा स्थिति को बदलना चाहती है? यदि इसका उत्तर 'हां' है तो विधेयक को स्थगित करना केवल एक औपचारिकता और दिखावा मात्र है।

तीन राज्यों में बंपर वोटिंग ने क्या संदेश दिया? क्या जनादेश अभी से साफ नजर आ रहा है?

नीरज कुमार दुबे ।

असम, केरल और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों में इस बार जबरदस्त मतदान ने लोकतंत्र की मजबूती का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। लगभग 80 प्रतिशत के औसत मतदान ने यह संकेत दिया है कि जनता न केवल राजनीतिक रूप से जागरूक है, बल्कि अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इतना ही नहीं, इस भारी मतदान ने राजनीतिक दलों की धड़कनें भी तेज कर दी हैं, क्योंकि हर दल इसे अपने पक्ष में जनसमर्थन के रूप में देख रहा है। हालांकि इस बंपर मतदान के वास्तविक मायने क्या हैं, यह समझने के लिए तीनों क्षेत्रों का अलग अलग विश्लेषण जरूरी है।

असम चुनाव

सबसे पहले बात असम की करें तो यहां का मतदान प्रतिशत न केवल पिछले चुनावों से अधिक रहा बल्कि कई क्षेत्रों में रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। कुल 126 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 85 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया, जो पहले के चुनावों के मुकाबले अधिक है। खास बात यह रही कि सोलह निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान नब्बे प्रतिशत से भी ऊपर पहुंच गया। दलगांव में तो मतदान लगभग 95 प्रतिशत के करीब रहा, जो राज्य में सबसे अधिक है। असम में चुनावी मुकाबला मुख्य रूप से दो ध्रुवों के बीच रहा। एक ओर भाजपा के नेतृत्व वाला सत्तारूढ़ गठबंधन है जो लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष गठबंधन सत्ता में वापसी के लिए संघर्षरत है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय दल भी कुछ सीटों पर प्रभाव डालने की स्थिति में हैं। यहां मतदान का एक महत्वपूर्ण पहलू क्षेत्रीय असमानता के रूप में सामने आया। निचले असम के क्षेत्रों में, जहां अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या अधिक है, वहां मतदान प्रतिशत अत्यधिक रहा। बरपेटा, बोंगाईगांव और धुबरी जैसे जिलों में मतदान नब्बे प्रतिशत से ऊपर दर्ज किया गया। इसके विपरीत ऊपरी असम के क्षेत्रों में मतदान अपेक्षाकृत कम रहा। इससे यह संकेत मिलता है कि चुनावी उत्साह उन क्षेत्रों में अधिक था जहां मुकाबला अधिक तीखा है। हालांकि मतदान के दौरान कुछ स्थानों पर हिंसा की घटनाएं भी सामने आईं, लेकिन कुल मिलाकर मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही। भारी मतदान को लेकर सत्तारूढ़ नेतृत्व ने इसे ऐतिहासिक बताया और इसे जनता के विश्वास का प्रतीक माना।

केरल चुनाव

अब केरल की बात करें तो यहां का चुनाव परंपरागत रूप से दो प्रमुख गठबंधनों के बीच होता रहा है। इस बार भी मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ वाम मोर्चा और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ मोर्चे के बीच रहा, जबकि तीसरा विकल्प बनने की कोशिश कर रहा भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में लगा है। केरल में लगभग 77 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया, जो पिछले चुनाव से अधिक है। आंकड़ों के मुताबिक कोझिकोड जिले में सबसे अधिक मतदान दर्ज किया गया, जबकि कुछ क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम मतदान हुआ। केरल में इस बार चुनाव का मुख्य सवाल यह रहा कि क्या सत्तारूढ़ गठबंधन लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटेगा या फिर विपक्ष वापसी करेगा? उच्च मतदान को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों ने अलग अलग दावे किए हैं। सत्तारूढ़ पक्ष इसे अपनी नीतियों के समर्थन के रूप में देख रहा है, जबकि विपक्ष इसे बदलाव की इच्छा का संकेत बता रहा है। हम आपको बता दें कि उत्तर केरल यानी मलाबार क्षेत्र इस बार भी चुनावी परिणामों की कुंजी माना जा रहा है। यहां की साठ सीटों पर तीनों प्रमुख राजनीतिक धाराओं की नजर है। पिछले चुनाव में इस क्षेत्र में सत्तारूढ़ दल को बड़ी सफलता मिली थी, लेकिन इस बार विपक्ष यहां बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा है। कई सीटों पर कड़ा मुकाबला और अस्सी प्रतिशत से अधिक मतदान इस क्षेत्र को और भी महत्वपूर्ण बना देता है।

पुडुचेरी चुनाव

अब पुडुचेरी की बात करें तो यहां सबसे अधिक मतदान दर्ज किया गया, जो लगभग नब्बे प्रतिशत के करीब रहा। यह पिछले सभी रिकॉर्ड को पार करता हुआ दिखाई देता है। यहां मुकाबला मुख्य रूप से दो गठबंधनों के बीच है। एक ओर सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन है तो दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष।

पुडुचेरी में चुनावी मुद्दों में राज्य का दर्जा, बेरोजगारी और जल प्रदूषण जैसे विषय प्रमुख रहे। इसके अलावा एक नए राजनीतिक दल की एंट्री ने भी चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। उच्च मतदान से यह संकेत मिलता है कि जनता इन मुद्दों को लेकर गंभीर है और बदलाव या स्थिरता में से किसी एक को स्पष्ट रूप से चुनना चाहती है। तीनों राज्यों के आंकड़ों को मिलाकर देखें तो कुल मिलाकर पांच करोड़ से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया और कुल एक हजार नौ सौ से अधिक उम्मीदवार मैदान में रहे। यह संख्या इस बात को दर्शाती है कि लोकतंत्र में भागीदारी कितनी व्यापक है।

भारी मतदान से क्या संदेश मिला?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारी मतदान सत्ता परिवर्तन का संकेत है या फिर यह सत्तारूढ़ दलों के प्रति विश्वास को दर्शाता है? चुनावी विशेषज्ञों की राय इस पर बंटी हुई है। कुछ का मानना है कि जब लोग बड़ी संख्या में मतदान करते हैं तो यह बदलाव की इच्छा का संकेत होता है, जबकि अन्य इसे सरकार के प्रति संतोष के रूप में देखते हैं। वैसे कई विश्लेषकों का यह भी कहना है कि तीनों ही राज्यों में चुनाव प्रचार के दौरान जो बात सबसे प्रमुख तौर पर नजर आई वह यह थी कि सरकार के खिलाफ नाराजगी जरूर दिखी लेकिन सरकार बदलने का भाव जनता के बीच नहीं दिखा।

बहरहाल, यह कहा जा सकता है कि असम में क्षेत्रीय ध्रुवीकरण, केरल में परंपरागत मुकाबला और पुडुचेरी में सीधी टक्कर ने इन चुनावों को बेहद रोमांचक और निर्णायक बना दिया है। भारी मतदान ने लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने का काम किया है और यह साफ संकेत दिया है कि जनता अपने अधिकार को लेकर पहले से अधिक सजग है। वहीं कई विश्लेषकों का यह भी मानना है कि तीनों ही राज्यों में चुनाव प्रचार के दौरान सरकार के खिलाफ नाराजगी तो जरूर दिखी, लेकिन सरकार बदलने का स्पष्ट भाव जनता के बीच नजर नहीं आया। ऐसे में अब सबकी नजर मतगणना पर टिकी है, क्योंकि असली तस्वीर वहीं सामने लाएगी जो इस जनभागीदारी के पीछे छिपे जनमत को स्पष्ट करेगी।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने कदम ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/[illegible])

चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम, सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई गई अंतिम मतदाता सूची

देवरिया। निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक अहम पहल की है। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अंतिम प्रकाशित निर्वाचक नामावलियों की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही जनपद की सभी सात विधानसभा क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूचियां राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं, जिससे आमजन आसानी से अपनी जानकारी का अवलोकन कर सकें। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचक नामावलियां उपलब्ध कराईं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे मतदाता सूची का गंभीरता से अवलोकन करें तथा किसी भी प्रकार की आपत्ति या सुझाव निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करें, ताकि आवश्यकतानुसार सुधार किया जा सके। इस अवसर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट श्रुति शर्मा, एसडीएम अवधेश निगम, तहसीलदार केके पांडेय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दूसरे चरण में जिलाधिकारी ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में उत्कृष्ट योगदान देने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि यह कार्य अत्यंत जिम्मेदारी एवं संवेदनशीलता से जुड़ा है, जिसे सभी कार्मिकों ने पूरी निष्ठा के साथ संपन्न किया है। सम्मान समारोह में चयनित कार्मिकों को माला पहनाकर प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए गए तथा लंच बॉक्स एवं पानी की बोतल भेंट की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि इस तरह के सम्मान से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और वे भविष्य में भी बेहतर कार्य के लिए प्रेरित होते हैं।

विशेष पुनरीक्षण-2026- कुशीनगर में निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन, 23.21 लाख मतदाता दर्ज

कुशीनगर।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के तहत जनपद कुशीनगर में निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विधानसभा वार बूथ स्तर की मतदाता सूची सॉफ्ट व हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराई। उन्होंने बताया कि अंतिम प्रकाशन (10 अप्रैल 2026) के अनुसार जनपद में कुल 23,21,867 मतदाता दर्ज किए गए हैं, जिनमें 12,65,877 पुरुष, 10,55,903 महिला एवं 87 अन्य श्रेणी के मतदाता शामिल हैं। इससे पूर्व 6 जनवरी 2026 को आलेख्य प्रकाशन के समय 21,92,390 मतदाता थे, जबकि 27 अक्टूबर 2025 को पुनरीक्षण के दौरान यह संख्या 26,95,030 थी। पुनरीक्षण अवधि में दावे एवं आपत्तियां 6 जनवरी से 6 मार्च 2026 तक प्राप्त की गईं, जिनके आधार पर फार्म-6 के माध्यम से 1,31,702 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए तथा फार्म-7 से 2,225 नाम विलोपित किए गए। साथ ही डाटा मैपिंग न होने व लॉजिकल विसंगतियों के कुल 5,71,672 मामलों में नोटिस जारी कर शत-प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस कार्य में 2875 बीएलओ, 271 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं 7 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वहीं राजनीतिक दलों द्वारा 8587 बीएलए तैनात कर सहयोग प्रदान किया गया। पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ ऐप पर 6456 कॉल एवं एनजीएसपी पोर्टल पर प्राप्त 1680 शिकायतों का भी त्वरित निस्तारण किया गया। उन्होंने बताया कि अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची का निरीक्षण मतदाता अपने मतदेय स्थल, संबंधित कार्यालय अथवा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल नहीं हो पाया है, तो वह फार्म-6 भरकर बीएलओ के पास जमा कर सकता है या ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकता है। साथ ही उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे अपने नाम का सत्यापन अवश्य कर लें और निर्वाचन प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें।

निर्वाचक नामावली के अंतिम आलेख्य का हुआ प्रकाशन

महराजगंज।

जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में एसआईआर (विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान) के पश्चात आज राजनीतिक दलों के समक्ष निर्वाचक नामावली के अंतिम आलेख्य का प्रकाशन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने मतदाता सूची के प्रकाशन पर सभी राजनीतिक दलों को बधाई देते हुए कहा कि मतदाताओं को सूची में दर्ज कराने तथा आरओ, ईआरओ, सुपरवाइजर एवं बूथ लेवल अधिकारियों/कर्मचारियों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप शत-प्रतिशत मतदाता सूची का सफल प्रकाशन संभव हो सका है।

उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया। जिलाधिकारी ने फरेन्दा, नौतनवा, सिसवा, महराजगंज एवं पनियरा विधानसभा क्षेत्रों की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में कुल मतदाताओं की संख्या 17,92,128 है। अंतिम आलेख्य के प्रकाशन के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के

जनपद में कुल मतदाताओं की संख्या 17,92,128,

प्रतिनिधि अफजल अब्बास (जिला मंत्रासचिव), विनोद कुमार सिंह उपाध्याय (कांग्रेस), विद्यासागर यादव (जिलाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी), आनन्द श्रीवास्तव (नगर अध्यक्ष), राघवेन्द्र तिवारी (भारतीय जनता पार्टी), पशुपतिनाथ गुप्ता एवं दामोदर गोयल (जिला सचिव, आम आदमी पार्टी) उपस्थित रहे।

विधानसभावार विवरण

315- फरेन्दा- पुरुष 1,79,447, महिला 1,51,041, थर्ड जेंडर 23 – कुल 3,30,511

316- नौतनवा- पुरुष 1,80,453, महिला 1,46,731, थर्ड जेंडर 03 – कुल 3,27,187

317- सिसवा- पुरुष 1,97,682, महिला 1,66,810, थर्ड जेंडर 06 – कुल 3,64,498

318- महराजगंज- पुरुष 2,05,075, महिला 1,72,457, थर्ड जेंडर 19 – कुल 3,77,551

319- पनियरा- पुरुष 2,13,840, महिला 1,78,537, थर्ड जेंडर 04 – कुल 3,92,381

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची की प्रतियां भी उपलब्ध कराई

जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची की प्रतियां भी उपलब्ध कराई गईं। उन्होंने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने में सहयोग और समर्थन को लेकर धन्यवाद ज्ञापित किया। जिलाधिकारी ने सभी निर्वाचन कार्यालय की पूरी टीम सहित एसआईआर कार्य में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके अथक प्रयास के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सहयोग के बिना इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करना संभव नहीं था।

प्रभारी सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रमोद कुमार ने अवगत कराया कि कांग्रेस, भाजपा और सपा के प्रतिनिधियों को अंतिम आलेख्य उपलब्ध करा दिया गया है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) प्रशांत कुमार, अपर उजिलाधिकारी प्रेमशंकर पाण्डेय, प्रभारी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी प्रमोद कुमार यादव, प्रधान सहायक राजेश कुमार वर्मा, मुहम्मद आलम उपस्थित रहे।

देवरिया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कायाकल्प- 78 करोड़ का ट्रामा सेंटर और हाईटेक मशीनों से लैस हुआ मेडिकल कॉलेज

इलाज के लिए गोरखपुर-लखनऊ की दौड़ पर लगा लगाम; 55 आरोग्य मंदिरों और आधुनिक डायलिसिस-सीटी स्कैन से सुधरी सेहत

जिला अस्पताल के लिए भूमि की तलाश जारी, विधायक शलभ मणि के रिपोर्ट कार्ड में स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर

देवरिया। किसी भी जनपद की प्रगति का सबसे सटीक पैमाना वहां की चिकित्सा व्यवस्था होती है। देवरिया, जो कभी छोटी-छोटी जांचों और गंभीर स्थितियों में इलाज के लिए गोरखपुर या लखनऊ के भरोसे रहता था, अब अपने स्वास्थ्य ढांचे को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में बीते चार वर्षों में हुआ बदलाव इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। 2022 तक जिन सुविधाओं का यहाँ अभाव था, आज वहां 128-स्लाइस की आधुनिक सीटी स्कैन मशीन, क्रिटिकल केयर यूनिट, और बच्चों के लिए विशेष PICU वार्ड जैसी सुविधाएं धरातल पर क्रियाशील हैं। सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी द्वारा साझा किए गए स्वास्थ्य सेवाओं के रिपोर्ट कार्ड के अनुसार, जिले के स्वास्थ्य ढांचे को तीन स्तरों पर मजबूत किया गया है। पहला, मेडिकल कॉलेज को उच्चीकृत करना; दूसरा, ग्रामीण इलाकों में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का जाल बिछाना; और तीसरा, ब्लॉक स्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को जिला अस्पताल की तर्ज पर विकसित करना। इसी कड़ी में गौरी बाजार CHC अब

एक मॉडल के रूप में उभरा है, जहां अब सिजेरियन ऑपरेशन, हड्डी के ऑपरेशन और टेलीमेडिसिन जैसी विशेषज्ञ सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही सुलभ हो गई हैं। आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए मेडिकल कॉलेज परिसर में प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र की स्थापना एक बड़ी राहत साबित हो रही है, जहां बाजार से काफी कम कीमतों पर दवाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, 78 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से बन रहा ट्रामा सेंटर भविष्य में आपातकालीन स्थितियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ मेडिकल शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसके तहत मेडिकल छात्रों के लिए लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत से नए हॉस्टल निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। हालांकि, विकास के इस दावों के बीच जिला अस्पताल के लिए स्वतंत्र भूमि की उपलब्धता अब भी एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती बनी हुई है। विधायक के अनुसार, इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने पीपीपी मॉडल के तहत एक भावनात्मक पहल भी की है, जिसमें भूमि दान करने वालों के पूर्वजों के नाम पर अस्पताल का नामकरण करने का विकल्प खुला रखा गया है। 55 नए आरोग्य आयुष्मान मंदिरों की स्थापना ने प्राथमिक उपचार को गांवों के दरवाजे तक पहुँचाया है। अब चुनौती इन सुविधाओं की गुणवत्ता को निरंतर बनाए रखने और विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की है, ताकि करोड़ों के ये उपकरण केवल शो-पीस बनकर न रह जाएं।

वाराणसी में आयोजित राष्ट्रीय सहकारी कार्यशाला में जिलाधिकारी ने प्रस्तुत किया सहकारिता आंदोलन के विकास का खाका

महराजगंज।

वाराणसी में आयोजित राष्ट्रीय सहकारी कार्यशाला में पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि जनपद के रूप में जनपद महराजगंज द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में किये जा रहे नवाचारी प्रयासों और प्राप्त विशिष्ट उपलब्धियों पर आधारित एक बृहद प्रेजेंटेशन कार्यक्रम में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रीय सहकारी कार्यशाला में पूरे देश के विभिन्न राज्यो के प्रमुख सचिव, रजिस्ट्रार, भारत सरकार के सचिव सहित शीर्ष स्तर के अधिकारी शामिल हुए। ऐसे में जनपद महराजगंज के उपलब्धियों को देश स्तर पर प्रस्तुत करना एक उल्लेखनीय उपलब्धि रही।

प्रस्तुतिकरण में जनपद में सहकारिता के विकास के लिए किए जा रहे नवाचारी प्रयासों को जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित सहकार से समृद्धि योजना अंतर्गत जनपद में 62 पैक्स द्वारा ट्रस्ट का संचालन किया जा रहा है। 03 समितियो द्वारा जन औषधि केंद्र का संचालन किया जा रहा है। 09 नए एम-पैक्स का गठन किया जा चुका है। 50 कंप्यूटरीकृत समितियो द्वारा ई- डिस्ट्रिक्ट की सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही है। हाल ही में चलाए गए सदस्यता अभियान के अंतर्गत जनपद महराजगंज ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए 1 लाख 30 हजार सदस्य बनाया था और 2 करोड़ 20 लाख रुपये की शेयर पूंजी हासिल की गई थी।

वर्ष 2022-23 में जनपद की 56 समितियो का जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण का कार्य जनपद स्तर पर कराया गया था, जो अपने तरह का इकलौता मॉडल था। बाद में पूरे प्रदेश में इसे लागू किया गया था। कंप्यूटरीकरण योजना अंतर्गत प्रथम और द्वितीय चरण में चयनित 50 समितियो को ई-पैक्स में बदला गया है, जहाँ सभी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन माध्यम से हो रहे हैं। इसी प्रकार जिला सहकारी बैंक को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए एक समन्वित और एकीकृत मॉडल तैयार किया गया है। दुग्ध, मत्स्य और पैक्स द्वारा किये जा रहे बैंकिंग लेन देन को जिला सहकारी बैंक से जोड़ा जा रहा है।

समितियो के अतिरिक्त सदस्यों के खाते भी जिला सहकारी बैंक में खोले जा रहे है। इससे एक तरफ जिला सहकारी बैंक के डिपाजिट में वृद्धि हो रही है तो दूसरी तरफ नए खातों की संख्या भी बढ़ी है। इसी प्रकार अल्पकालिक ऋण वितरण में भी अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2020-21 में जहाँ जिला सहकारी बैंक गोरखपुर द्वारा 391 लाख का ऋण वितरण किया गया था, वही 2025-26 में यह आंकड़ा बढ़ कर लगभग 49 करोड़ पहुँच गया है। जिन समितियो में बिजली की समस्या थी, उन समितियो में प्रदेश सरकार के सहयोग से सोलर रूप टॉप लगाया जा रहा है। कुल 19 समितियो में सोलर रूप टॉप लगाया जा चुका है। शेष में भी चरणबद्ध तरीके से लगाया जाना है। जिलाधिकारी ने बताया कि वर्ष 2023-24 तक जनपद में स्थिति कुल 96 समितियो में मात्र 61 ही क्रियाशील थी। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त 10 लाख की ब्याजमुक्त क्रेडिट लिमिट से अब 95 समितियाँ क्रियाशील हो चुकी है। इससे समितियो द्वारा किया जा रहा उर्वरक व्यवसाय 2023-24 में 56 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 86 करोड़ तक पहुँच गया है। प्रस्तुतिकरण के दौरान आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उत्तर प्रदेश द्वारा सदस्यता अभियान में उल्लेखनीय उपलब्धि हेतु जनपद महराजगंज की प्रशंसा की गई तथा भविष्य में और बेहतर कार्य करने की शुभकामना दी गई।

मेगा प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन, 201 छात्र-छात्राओं ने किया प्रतिभाग

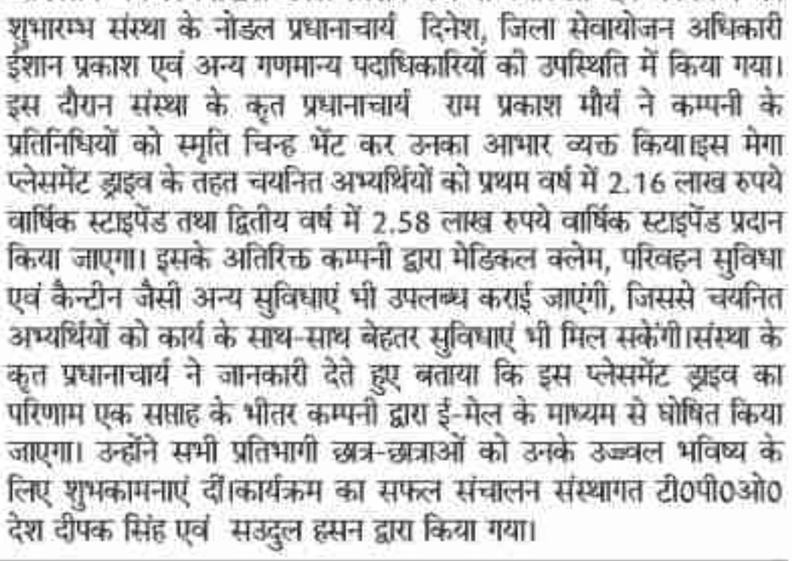

महराजगंज। संस्था महामाया आईटी0 पॉलिटेक्निक में विशिष्ट सेवायोजन सप्ताह के द्वितीय चरण के तहत जॉन डियर इंडिया कम्पनी द्वारा एक भव्य मेगा प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के कुल 201 छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया और रोजगार के सुनहरे अवसर प्राप्त करने की दिशा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में कम्पनी की ओर से सीनियर हायरिंग मैनेजर हर्ष दरियाल एवं ऑपरेशन मैनेजर निखिल काले विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारम्भ संस्था के नोडल प्रधानाचार्य दिनेश, जिला सेवायोजन अधिकारी ईशान प्रकाश एवं अन्य गणमान्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। इस दौरान संस्था के कृत प्रधानाचार्य राम प्रकाश मौर्य ने कम्पनी के प्रतिनिधियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका आभार व्यक्त किया।इस मेगा प्लेसमेंट ड्राइव के तहत चयनित अभ्यर्थियों को प्रथम वर्ष में 2.16 लाख रुपये वार्षिक स्टाइपेंड तथा द्वितीय वर्ष में 2.58 लाख रुपये वार्षिक स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कम्पनी द्वारा मेडिकल क्लेम, परिवहन सुविधा एवं कैन्टीन जैसी अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे चयनित अभ्यर्थियों को कार्य के साथ-साथ बेहतर सुविधाएं भी मिल सकेंगी।संस्था के कृत प्रधानाचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्लेसमेंट ड्राइव का परिणाम एक सप्ताह के भीतर कम्पनी द्वारा ई-मेल के माध्यम से घोषित किया जाएगा। उन्होंने सभी प्रतिभागी छात्र-छात्राओं को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।कार्यक्रम का सफल संचालन संस्थागत टी0पी0ओ0 देश दीपक सिंह एवं सउदुल हसन द्वारा किया गया।

बारिश में इस बार दिल्ली नहीं होगी परेशान, एक्शन में आई रेखा गुप्ता सरकार, उठाया यह कदम

नई दिल्ली।

दिल्ली में हर साल बारिश के मौसम में सड़कों पर पानी भरने की समस्या को देखते हुए सरकार ने इस बार पहले से तैयारी शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में जलभराव और नालों की सफाई को लेकर बड़ी बैठक की. बैठक में मुख्य सचिव राजीव वर्मा के साथ लोक निर्माण विभाग , दिल्ली नगर निगम, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली छावनी बोर्ड के बड़े अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि राजधानी के सभी बड़े और छोटे नालों से गाद निकालने का काम 30 जून तक हर हाल में पूरा होना चाहिए. उन्होंने

अधिकारियों को चेतावनी दी कि कहीं भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बारिश शुरू होते ही लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी जलभराव से होती है. इसके साथ ही जिन इलाकों में हर साल पानी भरता है, वहां अलग से खास इंतजाम किए जाएं. मुख्यमंत्री रेखा ने अधिकारियों को ऐसे सभी स्थानों की सूची बनाने और वहां पहले से मशीन, कर्मचारी और जरूरी सामान रखने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार चाहती है कि बारिश शुरू होने से पहले ही नालों की सफाई पूरी हो जाए, ताकि पानी आसानी से निकल सके. बैठक में यह भी कहा गया कि दिल्ली सरकार अब ऐसी नई योजना पर काम कर रही है, जिसमें सड़कों से पानी निकालने के लिए बार-बार पंप लगाने की जरूरत कम पड़े. इसके लिए पुराने ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत किया जाएगा और जहां जरूरत होगी वहां नई लाइनें डाली जाएंगी. सरकार खास तौर पर मिंटो रोड मॉडल पर काम कर रही है. मिंटो रोड उन जगहों में से है जहां हर साल बारिश में सबसे ज्यादा पानी भरता था. कई बार वहां गाड़ियां बंद हो जाती थीं और लंबा जाम लग जाता था. पिछले कुछ महीनों में वहां जल निकासी की नई व्यवस्था बनाई गई है. अब सरकार चाहती है कि उसी तरह का काम दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी किया जाए. दिल्ली में हर साल मानसून के दौरान कई जगहों पर लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है. आईटीओ, मिंटो रोड, जखीरा अंडरब्रिज, लोधी रोड, जहांगीरपुरी और करोला-कंझावला रोड जैसे इलाकों में अक्सर सड़कें तालाब बन जाती हैं.

एआईएमआईएम ने कबीर की पार्टी से गठबंधन तोड़ा

नई दिल्ली । असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया है। दोनों पार्टियों ने 25 मार्च को पश्चिम बंगाल चुनाव साथ लड़ने की घोषणा की थी। अब एआईएमआईएम चुनाव में अकेले उतरेगी। एआईएमआईएम के एक्स हैंडल पर लिखा गया- हुमायूं कबीर के हालिया खुलासों ने यह दिखा दिया है कि बंगाल के मुसलमान कितने असुरक्षित हैं। एआईएमआईएम ऐसे किसी भी बयान से खुद को नहीं जोड़ सकती, जिसमें मुसलमानों की निष्ठा या ईमानदारी पर सवाल उठाए जाएं।

महिलाओं को 3 हजार महीना- 6 महीने में यूसीसी लागू होगा

कोलकाता । भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के लिए पार्टी का घोषणा पत्र यानी भरोसे का पत्र जारी किया। इसमें महिलाओं को 3 हजार महीना, युवा बेरोजगारों को 3 हजार महीना की मदद, पहले 6 महीने में यूसीसी लागू करना और सरकारी कर्मचारियों को 45 दिन में सातवां वेतनमान देने की घोषणा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पत्र जारी करते हुए कहा बंगाल की जनता के लिए पिछले 15 साल बुरे सपने के जैसे रहे हैं। ममता घुसपैठियों के जरिए तीसरी बार सीएम बनीं हैं। हम घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करेंगे। राज्य में दो फेज में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी है। रिजल्ट 4 मई को आएगा।

बंगाल चुनावों के लिए संकल्प पत्र

- छह महीनों में यूसीसी का

बंगाल में भाजपा का वादा

कार्यान्वयन
- घुसपैठियों के खिलाफ शून्य सहिष्णुता नीति
- अगले 45 दिनों में सातवें वेतन आयोग का कार्यान्वयन
- महिलाओं को प्रति माह 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता
- पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत सहित भाजपा योजनाओं का

कार्यान्वयन
- सभी के लिए कानून व्यवस्था और सुरक्षित सीमाएँ सुनिश्चित करना
- भाजपा बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के लिए वंदे मातरम संग्रहालय का निर्माण करेगी
- राज्य पुलिस सहित बंगाल की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण
- बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता
- प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत, केंद्र की 6,000 रुपये की वार्षिक सहायता के अतिरिक्त बंगाल 3,000 रुपये का योगदान देगा
- बंगाल में चार नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे
- बंगाल में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना को केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के साथ एकीकृत किया जाएगा
- प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए 15,000 रुपये; भ्रष्टाचार के कारण नौकरी से वंचित लोगों के लिए आयु में 5 वर्ष की छूट।
- चैतन्य महाप्रभु आध्यात्मिक सर्किट विकसित किया जाएगा, रवींद्रनाथ टैगोर के नाम पर सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा।

सांप पर भी भरोसा किया जा सकता है, लेकिन बीजेपी पर नहीं, चुनावी रैली में बरसीं ममता

कोलकाता । (वेबवार्ता) पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को भाजपा पर तीखा हमला किया। उत्तर 24 परगना जिले के टेंटुलिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा को असम के स्थानीय लोगों के वोटों पर भरोसा नहीं था। इसलिए पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए बाहर से लोग बुलाए। ममता ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश से 50,000 लोगों को ट्रेन में भरकर असम लाया गया। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के राज में देश की कोई भी एजेंसी निष्पक्ष नहीं रह गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि केसरिया पार्टी ने सभी एजेंसियों को खरीद लिया है। भाजपा पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा, एक साँप पर तो भरोसा किया जा सकता है, लेकिन भाजपा पर कभी नहीं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी और भाजपा के बीच जुबानी जंग काफी तेज हो गई है। रैली के दौरान मुख्यमंत्री ने वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 90 लाख नाम हटा दिए गए हैं। एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि इन 90 लाख नामों में से 60 लाख हिंदू और 30 लाख मुस्लिम हैं। उन्होंने असम के एनआरसी का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी 19 लाख नाम लिस्ट से बाहर किए गए थे, जिनमें 13 लाख हिंदू और 6 लाख मुस्लिम थे। ममता बनर्जी ने लोगों को आगाह किया कि वे भाजपा पर कभी विश्वास न करें। असम की 126 सीटों के लिए गुरुवार को मतदान हुआ था।

पवन खेड़ा को राहत- तेलंगाना हाईकोर्ट से मिली एक हफ्ते की अग्रिम जमानत

हैदराबाद । तेलंगाना हाईकोर्ट ने कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को असम में दर्ज एक मामले में एक हफ्ते की अग्रिम जमानत दे दी है। यह राहत शुक्रवार को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दी। कोर्ट की जज न्यायमूर्ति सुजाना कलासिकम ने कहा कि पवन खेड़ा को एक हफ्ते का समय दिया जाता है ताकि वह संबंधित कोर्ट में जाकर नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकें। इस दौरान उन्हें कुछ शर्तों के साथ गिरफ्तारी से राहत मिलेगी। दरअसल, यह मामला असम पुलिस द्वारा दर्ज किया गया है। पवन खेड़ा पर आरोप है कि उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल को दावा किया था कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास कई पासपोर्ट और विदेश में संपत्ति है, जिसकी जानकारी चुनावी हलफनामे में नहीं दी गई।

मणिपुर में पुलिस से हथियार छीनने के प्रयास के आरोप में छह लोग गिरफ्तार

इंफाल । मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में हुए बम विस्फोट के बाद लगाए गए कर्फ्यू का उल्लंघन करने एवं पुलिसकर्मियों से हथियार छीनने का प्रयास करने के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान यांगोइजम बोरिश सिंह (23), मंगसतानम डेविड सिंह (21), पंगमलम निवाश मेइती (22), लैतोनजाम रोमेन सिंह (22), फिरेनजाम टोनी (21) और निंगथौजम डेनिश सिंह (22) के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि उक्त आरोपियों को बृहस्पतिवार को हिंगांग थाना क्षेत्र के अहल्लुप मखा लेइकई इलाके से गिरफ्तार किया गया। उसने बताया कि कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों ने पुलिस कर्मियों पर हमला किया और उनसे हथियार छीनने की कोशिश की।

नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के रूप में आज ली शपथ, चारों सदनों के सदस्य बनने वाले बिहार के दूसरे सीएम

नई दिल्ली । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। अब वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपनी संसदीय पारी का नया आगाज करेंगे। उनके राज्यसभा जाने के साथ ही बिहार में नयी सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त होगा। राज्यसभा के सभापति सी पी राधाकृष्णन ने अपने कक्ष में एक संक्षिप्त समारोह में उन्हें उच्च सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। कुमार ने केंद्रीय मंत्री एवं सदन के नेता जे पी नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विधि एवं न्याय राज्य

मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की मौजूदगी में हिंदी में शपथ ली। जनता दल-यूनाइटेड (जदयू) के नेता एवं पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, कांग्रेस नेता जयराम रमेश तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता, सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी भी शपथ ग्रहण के दौरान मौजूद थे। कुमार के राज्यसभा सदस्य की भूमिका संभालने के साथ ही बिहार में उनके शासन का अंत हो गया है।

बृहस्पतिवार को दिल्ली पहुंचने पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में स्पष्ट किया कि अब वे केंद्रीय राजनीति में सक्रिय रहेंगे। उनके इस कदम से बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया तेज हो गई है। बता दें कि नीतीश कुमार ने 1985 में बिहार विधानसभा से अपनी पारी शुरू की थी। वे 6 बार लोकसभा सांसद रहे और मुख्यमंत्री बनने के बाद 4 बार विधान परिषद के सदस्य चुने गए। वहीं आज नीतीश राय सभा सदस्य के रूप में शपथ ली है। जिसके साथ उन्हें चारों सदनों के सदस्य होने का गौरव प्राप्त हो गया। नीतीश कुमार लालू यादव के बाद चारों सदनों के सदस्य बनने वाले दूसरे सीएम बन गए है।

मेरठ सेंट्रल मार्केट विवाद- सेक्टर-2 में लगे पलायन के पोस्टर, 859 अवैध निर्माण गिराने का है सुप्रीम आदेश

मेरठ । मेरठ सेंट्रल मार्केट प्रकरण को लेकर अब सेक्टर-2 में रहने वाले लोगों का दर्द खुलकर सामने आने लगा है। क्षेत्र के कई स्थानों पर स्थानीय निवासियों ने अपने घरों और दीवारों पर पलायन के पोस्टर लगा दिए हैं, जिससे इलाके में हलचल मच गई है। निवासियों का कहना है कि प्रशासन द्वारा प्रस्तावित सेटबैक प्रक्रिया उनके लिए बड़ी समस्या बन सकती है। उनका कहना है कि सेक्टर-2 में अधिकांश मकान छोटे-छोटे हैं और ऐसे में सेटबैक नियम लागू करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार यदि सेटबैक लागू किया गया तो किसी का बाथरूम तो किसी का ड्राइंग रूम खत्म हो जाएगा। इससे घर रहने लायक नहीं रहेंगे और लोगों

को मजबूरन अपने घर छोड़ने पड़ सकते हैं। लोगों ने सवाल उठाया कि अगर मकानों का हिस्सा टूटेगा तो वे आखिर रहेंगे कहां। उनका कहना है कि उन्होंने वर्षों की मेहनत से अपने छोटे-छोटे घर बनाए हैं और अब उन पर संकट खड़ा हो गया है। निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए समाधान निकाला जाए, ताकि आम लोगों को अपने ही घरों से बेघर होने की नौबत न आए। फिलहाल क्षेत्र में लगे पलायन के पोस्टर चर्चा का विषय बने हुए हैं और लोग इस मुद्दे को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं।

रिपोर्ट- ईरान ने अमेरिका से बातचीत से किया इनकार

तेल अवीव। ईरान ने पाकिस्तान में होने वाली सीजफायर डील में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ईरानी मीडिया फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार, ईरान ने कहा है कि जब तक लेबनान में सीजफायर लागू नहीं हो जाता वह बातचीत नहीं करेगा। इससे पहले अमेरिकी वेबसाइट वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी थी कि ईरानी डेलिगेशन गुरुवार शाम पाकिस्तान पहुंच गया है। इसमें संसद अध्यक्ष गालिबाफ और विदेश मंत्री अराघची शामिल हैं। हालांकि फार्स न्यूज ने इसे फेक बताया। इससे पहले 7 अप्रैल को अमेरिका और ईरान 2 सप्ताह के सीजफायर पर सहमत हुए थे। यह भी तय हुआ था कि दोनों देशों के नेता पाकिस्तान में मीटिंग के लिए मिलेंगे। बातचीत शनिवार को इस्लामाबाद में होगी है। इसके लिए अमेरिकी डेलिगेशन आज इस्लामाबाद पहुंचेगा।

अमेरिका-ईरान के बीच इन मुद्दों पर बातचीत होनी है

ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम- अमेरिका का कहना है कि ईरान में कोई संवर्धन नहीं होगा। ईरान को अपना सारा हाई-लेवल इनरिच यूरेनियम बाहर करना होगा और न्यूक्लियर फैसिलिटीज बंद या सीमित करनी होंगी।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज- दुनिया का बहुत सारा तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान अभी भी इसका नियंत्रण रखना चाहता है और टोल (फीस) लेने की बात कर रहा है। वहीं, अमेरिका चाहता है कि रास्ता पूरी तरह खुला और सुरक्षित हो, बिना किसी रुकावट या फीस के।

बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम- अमेरिका ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों पर रोक लगाना चाहता है।

सैंक्शंस हटाना- ईरान चाहता है कि सभी अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध तुरंत हटा दिए जाएं, फ्रोजन एसेट्स वापस मिलें और मुआवजा भी मिले।

***कहा- लेबनान में सीजफायर लागू होने तक कोई डील नहीं; कल पाकिस्तान में बातचीत होनी है**

मतदाता सूची फीज करने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, 13 अप्रैल को सीजेआई की पीठ करेगी सुनवाई

नई दिल्ली । पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची को फ्रीज करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। चुनाव आयोग के इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 13 अप्रैल को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले पर नई याचिका के साथ लंबित याचिकाओं पर भी विचार करने पर सहमति जताई। चुनाव आयोग ने पहले चरण के मतदान वाली विधानसभा सीटों के लिए नौ अप्रैल को मतदाता सूची को अंतिम रूप देते हुए फ्रीज कर दिया था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में होंगे, जबकि मतगणना 4 मई को होगी।

मोटर बोट बन गई काल

यमुना में भयानक हादसा- 10 लोगों की मौत, 12 घायल और पांच लापता

मथुरा । (वेबवार्ता) मथुरा के वृंदावन में यमुना नदी में शुक्रवार दोपहर को उस समय बड़ा हादसा हो गया, जब श्रद्धालुओं से भरा एक मोटर बोट अचानक पलट गया। जानकारी के मुताबिक मोटर बोट में करीब 25 से 30 लोग सवार थे, जो श्रृंगार घाट से नाव में बैठे थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोगों में चीख-पुकार शुरू हो गई। प्रत्यक्षदर्शी भूप सिंह, जो पुल पर सॉविदा कर्मचारी ने बताया कि मोटर वोट अचानक असंतुलित हो गई, जिससे उसमें सवार श्रद्धालु नदी में डूब गए। अब तक 10 से 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं। डीआईजी शैलेश पांडेय, जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह, एसपी सिटी राजीव कुमार और अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस गोताखोरों की मदद से लगातार सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। डीआईजी शैलेश पांडे ने बताया है कि 10 लोगों की मौत, 12 घायल और पांच लोग अभी लापता हैं। जिनकी तलाश जारी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बचाव दल जल्द ही सभी को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। हादसे में निकाले गए घायलों को तुरंत मांट सीएचसी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि यमुना पर चल रहे कार्य के कारण पैंटून पुल को हटाया गया था, जिससे संतुलन बिगड़ने की आशंका है। घटना के बाद नगर निगम के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है। जांच में यह बात भी सामने आ रही है कि 150 लोगों का दल लुधियाना, पंजाब और मुक्तेश्वर से आया है और ये सभी उनमें ही शामिल थे। बताया गया है जिस नाव में लोग सवार थे वो भी पलट कर डूब गई है और उसकी तलाश भी जारी है। जिसकी यह नाव है वो प्राइवेट नाविक था। हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताते हुए एक्स पर लिखा, जनपद मथुरा में नाव पलटने से हुई दुर्घटना में जनहानि अत्यंत दुःखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। संबंधित अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर बचाव व राहत कार्य संचालित करने और घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति एवं शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।

जस्टिस यशवंत वर्मा ने दिया इस्तीफा

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में तैनात जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। उनके दिल्ली वाले घर में भारी मात्रा में जले हुए नोट मिलने के मामले में उनके खिलाफ आंतरिक जांच चल रही थी। साथ ही महाभियोग की भी चर्चा थी। इसी बीच उन्होंने पद से त्याग पत्र दे दिया है। दिल्ली वाले घर में जले हुए कैश मिलने के बाद उनका स्थानांतरण इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया गया था। पांच अप्रैल 2025 को उन्होंने शपथ ग्रहण किया था। न्यायिक कार्य से उनको फिलहाल अलग किया गया था। उनके खिलाफ महाभियोग लाने के मामले में कमेटी का गठन किया गया है। कई सांसदों ने संसद में जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए नोटिस दिया था। फिलहाल जस्टिस वर्मा के खिलाफ आंतरिक जांच कमेटी जांच कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिए गए त्यागपत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा ने लिखा है- यद्यपि मैं आपके आदरणीय कार्यालय को उन कारणों से विवश नहीं करना चाहता, जिनके कारण मुझे यह पत्र प्रस्तुत करना पड़ रहा है। फिर भी अत्यंत पीड़ा के साथ मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से तत्काल प्रभाव से अपना त्यागपत्र दे रहा हूं। इस पद पर सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात रही है।